Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

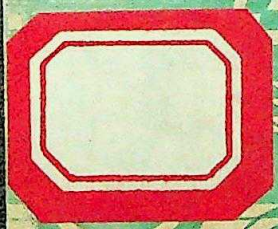

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान आदि
न लगायें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या ..... आगत संख्या.....

पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा। पुस्तक लेने के पहले पाठ्य पुस्तक की भली-भांति जांच कर लें। इश्यू होने के पश्चात फटी पुस्तक, विलुप्त पृष्ठो की कोई जिम्मेदारी पुस्तकालय की नहीं होगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

8143

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

प्रधानमंत्री के विचार

प्रकाशन विभाग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार

वर्ग संख्या.....,...आगत सख्या 3841

पुस्तक-वितरण की तिथि नोचे अंकित है। इस तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

प्रधान मंत्री के विचार

डाक प्रभाग द्वारा १९८४-१९८५

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अग्रहायण-पौष, 1891 ● दिसम्बर, 1969

बिक्री के लिए नहीं

निदेशक, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1
द्वारा प्रकाशित और राकेश प्रेस, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

3.43

सूची

बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों ?	...	...	1
सही दिशा में एक कदम	...	...	5
समाजवाद की ओर	...	...	12
आगे के काम	...	...	22
बैंकों की नई भूमिका	...	...	27
बैंकों से देश का हित साधन	...	...	31

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों ?

आज, सरकार ने भारत में स्थापित, चौदह बड़े बैंकों को ले लिया है। आर्डिनेंस जारी किया जा चुका है। यह खबर आपने अभी ही सुनी होगी। यह राष्ट्रीयकरण करना क्यों जरूरी था ? सरकार का इन बैंकों को ले लेना क्यों जरूरी था ? इसके बारे में और राष्ट्रीयकरण के बाद हम किस ढंग से इन बैंकों को चलाना चाहते हैं, इसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं।

बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका

पन्द्रह वर्ष पहले, उन्नीस सौ चौवन में, संसद में हमने सोशलिस्ट पैटर्न- यानी समाजवादी समाज—को अपनाने का फैसला किया था और यह तय हुआ था कि इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी सभी योजनाएं और नीतियां बनाएं। हमारा समाज गरीब और पिछड़ा हुआ है, हमें विकास करना है।

---

19 जुलाई 1969 को आकाशवाणी से प्रसारित 'राष्ट्र के नाम सन्देश'।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभिन्न तबकों—गरीब और अमीर—में विषमता कम करनी है। इसके लिए यह जरूरी है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के खास मोर्चों पर सरकार द्वारा, जनता का कब्जा हो। भारत प्राचीन है, लेकिन हमारा लोकतंत्र नया है और इसकी रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था चंद लोगों की मुट्ठी में न रहे। किसी भी मुल्क की अर्थ-व्यवस्था में बैंक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बैंक, अमीरों के पैसों की अमानतदार है। अगर यह कुशलता से चले तो जमा करने वालों का फायदा होता है। देश में जो करोड़ों छोटे-मोटे किसान, कारीगर, छोटे धन्धे करने वालों को अपने कारोबार के लिए कर्ज की जरूरत है, बैंक उनकी इस जरूरत को पूरा कर सकता है। व्यापार और उद्योग, चाहे बड़े हों या छोटे, बैंक से वाजिब दर पर कर्ज लिए बिना तरक्की नहीं कर सकते।

पढ़े, लिखे नौजवानों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है, उनको रोजगार और देश की सेवा के अवसर देने में बैंकों का बहुत बड़ा स्थान है। जो व्यापारी नहीं हैं, उन सबके लिए बैंक—रेलवे और डाक सेवा की तरह दैनिक जीवन में सार्वजनिक सुविधा का एक अंग है।

महान सामाजिक लक्ष्य

बैंक-प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है, जिसका संबंध हमारे लाखों देशवासियों के जीवन से है, और होना भी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि यह व्यवस्था, देश के सामाजिक आदर्शों से जुड़ी हो और राष्ट्र के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायक हो। इसलिए हमारे देश में यह मांग की जा रही है कि बड़े बैंकों पर सिर्फ सामाजिक नियन्त्रण ही नहीं, बल्कि जनता की मलकियत हो। कई देश जो समाजवादी नहीं हैं, उन्होंने भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। यही वजह थी कि 10-12 साल पहले हमने जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया और इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक बनाया। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने कई आर्थिक संस्थाओं द्वारा कृषि उद्योग को कर्ज देने का प्रबन्ध किया है। आज की कार्रवाई इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी।

यह मेरी आशा है कि इससे हमारी योजनाओं और नीतियों को असलियत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देने में हमें मदद मिलेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि और क्षेत्रों में भी राष्ट्रीयकरण आ रहा है। यह भी हमारा मकसद नहीं है कि जो पूंजी उत्पादन में लगी है उसे दूसरी ओर ले जाएं। विकास हमारा लक्ष्य है—खेतों और कारखानों में उत्पादन ज्यादा हो, पिछड़े क्षेत्र तरक्की करें, निर्यात बढ़े, आत्म-निर्भरता आए। ये तब हासिल हो सकता है जबकि हमारे साधन और अवसर अधिक हों, सीमित साधनों को एक जेब से दूसरी जेब में डालने से कोई लाभ नहीं। बड़े बैंक जनता के हाथ आ जाने से सट्टा बाजार और फिजूल कार्यों में पूंजी का लगाना बन्द हो जाएगा। अब तक ऐसा होता था, क्योंकि बड़े बैंकों से चन्द पूंजीपतियों का संबंध था। मैं विश्वास दिलाती हूं कि छोटे-बड़े उद्योग और व्यापार को वाजिब जरूरतों के लिए कर्ज की सुविधा बनी रहेगी। हमारी यह कोशिश होगी कि वास्तविक बचत के आधार पर बैंकों को कर्ज देने की शक्ति बढ़े, वह हमारे देश की और हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था की अनेक ज़रूरतों को पूरा करे।

तेज विकास के लिए राष्ट्रीयकरण

कुछ समय पहले हमने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति अपनाई थी, परन्तु इस राष्ट्रीयकरण के करने का महत्व यह है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति अब तेजी से कर सकें। अब तक हमारे बैंकों ने खेती, छोटे उद्योग-धन्धों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पूरी सहायता नहीं दी, उद्योग के क्षेत्र में आने-वाले नये लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया। बैंकों को थोड़े-से लोगों के कब्जे से छुड़ाना है। बैंक-व्यवस्था के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग का इन्तजाम करना, उनकी सेवा-शर्तों पर भी गौर करना है। इन उद्देश्यों को जल्दी पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। पर केवल राष्ट्रीय-करण कर देने भर से ही ये उद्देश्य नहीं पूरे होंगे।

बैंकों के पहले के नाम बने रहेंगे

कुछ अरसे के लिए इन बैंकों की व्यवस्था अलग ही बनी रहेगी। अगले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हफ्ते जब आपके बैंक खुलेंगे तो आपके साथ उनका रिश्ता पहले की तरह बना रहेगा।

आगे चलकर इन बैंकों के संगठन में परिवर्तन किया जाएगा। विशेषज्ञों द्वारा, अच्छी तरह जांच-पड़ताल और परामर्श के बाद जरूरी रद्दोबदल किए जाएंगे। शायद, आपको मालूम हो कि एक बैंक आयोग काम कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार, कैसी बैंक-व्यवस्था चाहिए, उस पर वह विचार कर रहा है।

कटिबद्ध प्रयास अपेक्षित

खेती, उद्योग और निर्यात में तरक्की के लिए हम तैयार हैं। जो माल विदेश से आता है, उसे पैदा करने को आज हम समर्थ हैं। हमारे किसानों, मजदूरों और उद्योगपतियों में एक नया उत्साह है। हमारी औद्योगिक शक्ति बढ़ी है। हमारे बीच आज ज्यादा कुशल मैनेजर और टेकनीकी लोग हैं। इन सब का सही उपयोग करने के लिए, यह जरूरी है, कि साधनों को संकल्प के साथ जुटाएं, और सूझ-बूझ से उत्पादन बढ़ाने में इस्तेमाल करें। इस नई योजना से, हमने एक बड़ा कदम उठाया है, और हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे महान देश के महान सपनों को साकार करने में, इससे मदद मिलेगी। मेरी आप सबसे विनती है कि सामाजिक लोकतंत्र के इस प्रयोग को सफल बनाने में आप सभी सहयोग दें। बैंकों के मैनेजर और कर्मचारियों से मेरा खास अनुरोध है कि वे बैंकों द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में, पूरा-पूरा सहयोग दें। बैंक, सेवा-संगठन हैं और मुझे यकीन है कि बैंक के मैनेजर और कर्मचारी, उन तमाम लोगों की विनम्र तथा समुचित सेवा करेंगे, जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा उनके पास जमा करते हैं।

विदेश नीति की तरह, आंतरिक नीति में भी हम अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ही ध्यान में रखते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारा एकमात्र उद्देश्य, हमारी गरीब जनता का भलाई और उनकी उन्नति है। हर समय, हमारी यही कोशिश रहेगी, कि उनका जीवन जल्दी से जल्दी सुखद बने।

सही दिशा में एक कदम

चौदह स्थापित बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अध्यादेश को अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में संसद् में जो बहस हुई है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। संसद से बाहर अन्य पत्रों आदि में भी जो राय जाहिर की गई हैं उनको भी मैंने देखा है। इस सम्बन्ध में प्राप्त अनेक पत्र, तार और जनता द्वारा प्रकट की गई राय से भी मैं परिचित हूं। मुझे कहना चाहिए कि सारे देश के लोगों में हुई प्रतिक्रिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो कदम हमने उठाया था उसको हमारे देशवासियों के एक बहुत बड़े बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

फिर भी ऐसे बहुत-से पेशेवर निराशावादी हैं, जिन्होंने आजादी मिलने के बाद के इन सभी वर्षों में निरन्तर निराशा और बर्बादी की भविष्यवाणियां की हैं। यह बात दूसरी है कि ये सब गलत साबित हुई। खुशी की बात है कि जितना शोर वे मचाते हैं, उसमें तर्क उतना ही कम होता है और न उसे अधिक जनता का समर्थन मिल पाता है जैसा कि हमारे माननीय मित्र श्री द्विवेदी पहले ही कह चुके हैं।

चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूर्णतया उचित है—शुद्ध आर्थिक दृष्टि से भी और उन व्यापक उद्देश्यों की दृष्टि से भी, जिन्हें हमने लाखों-करोड़ों देश-

---

29 जुलाई 1969 को लोकसभा में दिया गया भाषण।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वासियों की आशाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनाया है और भविष्य में भी अपनायेंगे।

कुछ ही वर्ष पहले 1954 में संसद ने समाजवादी ढंग के समाज की रचना का उद्देश्य स्वीकार किया था। इसके बाद सरकारी क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिससे और अधिक औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार निर्मित हुआ।

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तुलना बेकार है। हमारी अर्थव्यवस्था में इन दोनों क्षेत्रों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करनी हैं। लेकिन जब मैंने सरकारी क्षेत्र की आलोचना की तो उससे यह नहीं समझना चाहिए कि निजी क्षेत्र गुणों की खान है। वस्तुतः इस क्षेत्र का अब तक का इतिहास ऐसा नहीं है जिससे प्रेरणा या उत्साह बढ़े। अगर इस प्रकार के गलत प्रचार चलते रहे, जैसा कि किसी साथी ने बहस में कहा है तो सरकार के पास इस बात के काफी प्रमाण हैं कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी काफी खराब हालत चल रही है। अतः मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो सरकारी क्षेत्र का दिन-रात विरोध करते हैं और सदैव इसे नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं, वे कुछ अधिक उत्तरदायित्व और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करें। देश के व्यावसायिक बैंकों की कार्यविधि का जितना अध्ययन किया जाए उतनी ही यह धारणा बढ़ती है कि जिस कदम पर हम इस संसद में बहस कर रहे हैं वह अपरिहार्य और पूर्णतया अनिवार्य था।

बैंक व्यवसाय और दूसरे उद्योगों में बुनियादी अन्तर हैं। बैंकों में उनके शेयर होल्डरों की वित्तीय जोखिम लगभग नगण्य होती है। इन 14 बैंकों की कुल चुकता शेयर पूंजी कुल जमा धनराशि की 2·4 प्रतिशत थी। 31 दिसम्बर 1968 को इन बैंकों के पास 2,750 करोड़ रुपया जमा था। जबकि इनकी चुकता पूंजी केवल 28·5 करोड़ रुपया अर्थात् एक प्रतिशत से कुछ ही अधिक थी। इस प्रकार बैंक प्रबंधक लगभग अपना सारा धंधा जनता की पूंजी से चला रहे थे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरे देशों में

बैंक व्यवसाय का यह पहलू उन देशों में भी चिंता का विषय बना है जो समाजवाद में आस्था नहीं रखते। माननीय सदस्य इसे शायद भली भाँति जानते हैं। वस्तुतः अनेक देशों ने या तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है या उनकी कार्यविधि पर जबर्दस्त अंकुश लगा दिए हैं। फ्रांस ने अपने यहां के छः बड़े बैंकों में से चार का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी समझा। जो दो बैंक बचे हैं, वे कुल बैंक साधनों के बीसवें भाग के ही स्वामी हैं। इसी तरह इटली सरकार ने पांच बड़े बैंकों में से चार को सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया। स्वीडन की सरकार ने भी अपने यहां दो बैंकों की पूंजी सरकारी क्षेत्र में कर ली। इनको 1950 में मिला दिया गया।

लोगों ने सामाजिक नियंत्रण के बारे में यह सवाल उठाया है कि इसे कुछ और समय तक क्यों नहीं आजमाया जा सकता था। सामाजिक नियंत्रण में, विशेषज्ञ प्रबंधकों पर जोर देने जैसी कई उपयोगी विशेषताएं थीं जो वांछनीय हैं। सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था में कृषि, निर्यात और छोटे उद्योगों को भी ऊंची प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन सामाजिक नियंत्रण की कमजोरी यह थी कि कई बैंकों में जो लोग पहले नीति निर्धारित करते थे, वे तब भी किसी न किसी रूप में कभी-कभी निदेशक मंडल के पुराने अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की मार्फत नीतियों को प्रभावित कर रहे थे। हो सकता है, बैंकों ने आदेशों और निर्देशों का पालन किया हो, जैसा कि कुछ ने किया भी। लेकिन जो लोग किसी नीति पर तहे दिल से उत्साहपूर्वक अमल करते हैं और जो केवल आदेशों के कारण नीति का पालन करते हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। कई बैंकों ने इन निर्देशों का पालन नहीं भी किया, अतः हम उन साधनहीन वर्गों के अधैर्य और नैराश्य की अवहेलना नहीं करते रह सकते थे, जो स्वावलंबी बनने के लिए हमारी मदद चाहते हैं।

विदेशी बैंकों को क्यों छोड़ा गया ?

यहां यह भी पूछा गया है कि हमने इस विधेयक में विदेशी बैंकों को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्यों नहां शामिल किया है ? विदेशी बैंक एक विश्वव्यापी संगठन के अंग हैं और इस कारण वे निर्यातकों और आयातकों को कुछ विशेष सुविधाएं देने की स्थिति में हैं। इस तरह की सुविधाओं के लिए विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाओं की संख्या बहुत कम है।

विदेशी बैंक उन विदेशी ग्राहकों को नज़दीक से जानते हैं, जिनसे भारतीय निर्यातकों का व्यवहार चलता है। इस तरह से विदेशी बैंकों का, विदेशी मुद्रा में कर्ज देने और अपने मुख्य कार्यालय की ओर से उनका नियमन करने, पर्यटकों को सेवाएं प्रदान करने और भारत में उपलब्ध वाणिज्य के अवसरों की जानकारी अपने कार्यक्षेत्र वाले देशों को कराने में विशेष महत्व है। साथ ही, विदेशी बैंकों पर कड़े नियम लागू हैं। इस सम्बन्ध में एक नियम यह है कि विदेशी बैंक बंदरगाहों तक ही अपना कारोबार सीमित रखें। केवल ऐसे बैंकों को ही देश के अंदरूनी हिस्सों में कारोबार करने की छूट है, जिनकी शाखाएं वहां पहले से काम कर रही हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया किसी विदेशी बैंक को विस्तार की अनुमति तभी देगा, जब विदेशी व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से भारतीय ग्राहकों के लिए इन बैंकों की अधिक कुशल सेवाएं जरूरी समझी जाएंगी।

छोटे बैंक

एक अन्य आलोचना छोटे बैंकों को छोड़ देने के बारे में थी। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य कृषि, छोटे उद्योगों और निर्यात को तेजी से बढ़ावा देना, नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और सभी पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना है। जिन बैंकों के जमा खातों में 50 करोड़ या इससे अधिक राशि है, उनकी शाखाएं अनेक राज्यों में हैं। इसके विपरीत छोटे बैंकों का कार्यक्षेत्र कुछ खास-खास क्षेत्रों में ही है। विधेयक में शामिल 14 बैंकों का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक है, इसलिए ये छोटे बैंकों के मुकाबले सरकारी उद्देश्यों पर अधिक अच्छी तरह अमल कर सकने की स्थिति में हैं। छोटे बैंक मुख्यतः छोटे कर्जदारों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। उनके आंकड़ों से स्पष्ट है कि उनके कर्ज का औसत आकार कहीं छोटा होता है। वे उस समुदाय के हिस्से हैं, जिसमें उनका कारोबार है। छोटे व्यापारी और उद्योगपति उनकी कार्यविधि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं। जहां तक नियमन का प्रश्न है, छोटे और बड़े बैंकों में कुछ अन्तर किया जा रहा है।

इन सब बैंकों के संचालन के लिए कोई विशाल केन्द्रीय संस्था गठित करने का हमारा इरादा नहीं है। अलबत्ता, हमें केन्द्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा, लेकिन, हर बैंक को स्वायत्तता प्राप्त होगी और निदेशक मंडल को सुनिश्चित अधिकार दिए जाएंगे। हम निर्देश अवश्य देंगे, लेकिन वे नीति और आम मामलों के सम्बन्ध में ही होंगे—किसी सौदे या विशेष ऋण के बारे में नहीं। हम लोग अत्यधिक हस्तक्षेप के खतरों से हमेशा सावधान रहेंगे—चाहे वह राजनैतिक कारणों से प्रेरित हो या अन्य कारणों से।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह 14 बैंक रिज़र्व बैंक के प्राधिकार से बाहर रहेंगे। यह ठीक बात नहीं है, क्योंकि वे शिड्यूल्ड बैंक हैं और उनके ऊपर रिजर्व बैंक का अधिकार रहेगा। इससे रिजर्व बैंक का महत्व कम नहीं होगा। वास्तव में यह और अधिक महत्वपूर्ण और सोद्देश्य होगा और रिजर्व बैंक का संगठन इससे मजबूत होगा, जिससे वह नई दिशा में अ सर हो सकेगा।

नौकरशाही नहीं

मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा भी है कि बैंकों में नौकरशाही हावी न हो। हमें इन बैंकों के उद्यम, उत्साह और निजत्व को भी सुरक्षित रखना होगा। यह सब हम इस तरह करना चाहते हैं कि स्वस्थ प्रतियोगिता या उद्यम की भावना खत्म न हो जाए।

इस अवसर पर मैं शेयरहोल्डरों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि क्षतिपूर्ति की जो राशि तय की गई है, वह उचित और न्यायसंगत है। जैसा कि माननीय न्यायमंत्री ने स्पष्ट किया है। हमारी यह कोशिश भी है कि क्षतिपूर्ति की अदायगी यथासम्भव जल्द कर दी जाए।

हिस्सेदारों को उचित मुआवजा

एक सदस्य ने शंका की है कि सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अदायगी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिस्सेदारों के लिए कठिनाइयां पैदा करेगी। मैं इसका जोरदार शब्दों में प्रतिरोध करना चाहती हूं। हाल में ही भारत सरकार ने 4·25 प्रतिशत ब्याज पर 7 साल के ऋणपत्र जारी किये थे। ये प्रतिभूतियां थोड़ी-सी बढ़ोतरी पर बाजार में बिक जाती हैं। 5·5 प्रतिशत ब्याज वाले 30 वर्षीय ऋणपत्र भी बढ़ोतरी पर बिक जाते हैं। इसलिए यह कहना, कि इन प्रतिभूतियों से शेयर-होल्डरों को पूंजीगत हानि होगी, बहुत खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना बयान है।

यह भी होता है कि समाज के अपेक्षाकृत गरीब वर्ग को प्रतिभूतियों को वाजिब से कम मूल्य पर बेचने के हेतु प्रेरित करने के लिए उनके वास्तविक मूल्य के बारे में शंकाएं फैला दी जाती हैं। मुझे आशा है कि कोई ऐसी बातें नहीं कहेगा, जिससे इस तरह का शोषण हो। ये प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय होंगी और इन्हें बेचा जा सकेगा। इनके बेचने से घाटा नहीं होना चाहिए।

बैंकों के प्रबंधकों और कर्मचारियों को मैं आश्वासन देना चाहती हूं कि हम उनके जायज हितों की देखभाल करेंगे। हम उनसे सहयोग एवं सद्भाव की आशा रखते हैं। देश और बैंक व्यवसाय के हितों को नजरंदाज करते ए आंदोलन का रवैया अब नहीं अपनाया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि कर्मचारी और प्रबंधक सहयोग करेंगे और जिम्मेदारी का रवैया अपनाएंगे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बैंक कर्मचारियों के अनेक प्रतिनिधियों ने, जो मुझसे मिलने आए, यह आश्वासन दिया कि इस कार्य में उन का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा जिससे यह कदम सफल हो और सही दिशा में अग्रसर हो। उद्योग हो या व्यापार अथवा खेती, सब की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा।

पवित्र धरोहर

मैं पहले ही इस बात का आश्वासन दे चुकी हूं कि खातेदारों द्वारा जमा रकमों को ये बैंक पवित्र न्यास समझेंगे। भारत की जनता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लेन-देन करने की अभ्यस्त हो चुकी है। सकल जमा पूंजी का एक-तिहाई स्टेट बैंक और उसकी सहायक संस्थाओं में है, लेकिन किसी ने भी यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
नहीं कहा कि खातेदारों के हितों पर किसी प्रकार से आंच आई है। मैं नहीं कहती कि स्टेट बैंक आदर्श है, लेकिन निश्चय ही समाज को सुविधाएं देने में वह निजी बैंकों के मुकाबले, कार्यकुशलता या कर्ज देने में पीछे नहीं है। डाकखानों के बचत बैंक सुदूर देहाती इलाकों में—जनता को बैंक से व्यवहार करने की आदत डालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। 1967 के अंत में डाकखानों के बचत बैंकों में डेढ़ करोड़ खातेदारों का 700 करोड़ रुपया जमा था।

सरकार का कटु से कटु आलोचक भी नहीं कह सकता कि डाकखानों के बचत खातों में रुपया जमा करने वालों ने कभी महसूस किया हो कि उनके हित सुरक्षित नहीं हैं।

व्यापक सेवा

आम जनता को हम बेहतर और पहले से व्यापक सेवा का आश्वासन देते हैं। देश के विभिन्न भागों में बैंक की सुविधाओं का विकास बहुत असंतुलित रहा है। उन राज्यों में बैंक सुविधाएं बढ़ाने की तात्कालिक आवश्यकता है, जिनमें बैंकों की कमी है। विकसित राज्यों में भी बैंकों की सुविधाएं शहरी इलाकों—खासकर बड़े शहरों तक ही सीमित हैं, जबकि छोटे कस्बों और देहाती इलाकों में वे बहुत कम हैं। अलग-अलग राज्यों में ऋण और जमा अनुपात के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कई राज्यों में यह अनुपात बहुत कम है, जैसे—असम, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि। इससे यह शिकायत पैदा हुई कि बैंक कुछ इलाकों में जमा रकम का उपयोग अन्य इलाकों में करके क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा देते हैं। ये प्रवृत्तियां दुरुस्त की जा सकती हैं और संतुलित क्षेत्रीय विकास की नीति, जिस पर अक्सर जोर दिया गया है, तभी लागू की जा सकती है, जब बैंकों पर सरकारी नियंत्रण हो।

माननीय सदस्यों को मैं यह आश्वासन देना चाहूंगी कि इस विधेयक को लागू करते समय सरकार उस व्यापक हार्दिक समर्थन की अधिकारी बनने की कोशिश करेगी जो उसे इस सम्बन्ध में मिला है। हम इस विधेयक को केवल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
अधिक ऋण देने के लिए ही नहीं, बल्कि सोद्देश्य ऋण देने के लिए भी लागू करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य उन गम्भीर और गहरी समस्याओं को सुलझाने का है जो आजादी मिलने के समय से समाज के विभिन्न वर्गों और देश के विभिन्न भागों के सामने रही हैं।

माननीय विरोधी सदस्यों से मैं इस बात में सहमत हूं कि यह कदम ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन यह कदम सही दिशा में अवश्य है। अतः मैं सभी सदस्यों से यह अनुरोध करती हूं कि जो लोग इसके सफल कार्यान्वयन में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी सहायता हमें चाहिए। वे हमें सुझाव और नए विचार दें जिन पर हम निश्चय ही विचार करेंगे ताकि इस को इस तरह लागू किया जा सके कि उनको या देश के आम लोगों को निराशा न हो।

समाजवाद की ओर

सदन में इस बहस से कई अजीब बातों का पता चला है—कौन से लोग इस विधेयक का समर्थन करते हैं और क्यों? और कौन लोग इसका समर्थन नहीं करते और क्यों?—बहुत-से विचित्र तर्क और सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए हैं और विचित्र उपमाएं दी गई हैं। जो भी कारण हो माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का जो आम समर्थन किया है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूं। मैं यहां पर इसके विषय में अपने विचार पहले ही प्रगट कर चुकी हूं और जो मुद्दे उठाए गए उन पर पहले ही कहा जा चुका है।

---

7 अगस्त 1969 को राज्यसभा में दिया गया भाषण।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फिर भी मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि एक दशक से भी अधिक हो गए जब कि संसद ने देश के सामने समाजवादी ढांचे का लक्ष्य प्रस्तुत किया था। हमारे विचार से इसका मतलब यह नहीं था कि उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो परन्तु हमने यह जरूर कल्पना की थी कि जनहित को ध्यान में रखते हुए नियन्त्रण के अधीन निजी उद्योग के लिए काफी बड़ा क्षेत्र रहे। समाज के समाजवादी ढांचे का लक्ष्य स्वीकार करने के बाद हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व के अन्तर्गत ले आवें। इसका यह भी अर्थ है कि सरकार ऐसे उपाय करे कि आर्थिक विकृतियों के कारण हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था कमजोर न होने पावे।

बैंकों का महत्व

हर देश में, उन देशों में भी जहां पूंजीवादी व्यवस्था का जोर है यह माना जाता है कि बैंकों और इसी प्रकार की वित्तीय संस्थाओं का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। हमारी अर्थव्यस्था में, जिसका विकास हो रहा है, और जहां बहुत वर्षों के विकास को दो चार पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में ही प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, बैंकों का महत्त्व उन्नत अर्थव्यवस्था-वाले देशों से अधिक है। हमें शहर और देहात सब जगह हर वर्ग की जनता में पैसा बचाने की आदत डालनी चाहिए। हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि इस बचत का उपयोग हमारी योजनाओं और नई योजना के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार हो। हमने अपनी नई योजना अभी शुरू की है और इसमें हम नए और छोटे औद्योगिकों को अधिक अवसर देना चाहते हैं। हम यह भी प्रबन्ध करना चाहते हैं कि देश के अनेक भागों में खेती में जो क्रान्ति हो रही है वह सफल हो और हमारे प्रगतिशील किसानों के प्रयत्नों को रुपये की कमी से बाधा न पहुंचे। आर्थिक विकास के साथ देश में आर्थिक शक्ति और अधिकारों का जो केन्द्रीयकरण हुआ है, उसको भी हम दूर करना चाहते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि निजी क्षेत्र में एकाधिकार के बढ़ने का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि बड़े उद्योग-व्यापार समूहों का बैंकों के ऊपर कब्जा रहा है। निजी बैंकों की कार्यकुशलता के बहुत गुण गाए गए हैं फिर भी हम देखते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी उनमें जमा रकम राष्ट्रीय आय की केवल 16 प्रतिशत होती है और मैं समझती हूं तथा अन्य माननीय सदस्यों ने भी बताया है कि देश में अभी भी 13 जिले ऐसे हैं जहां एक भी बैंक नहीं है और बैंकों का अधिकांश लेन-देन बड़े नगरों में ही होता है। क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि बैंकों की सुविधाओं का विस्तार एकांगी हुआ है और देश के विभिन्न भागों में लोगों की जमा को बटोरने में और उचित कामों के लिए ऋण देने में बैंक बहुत कुशल नहीं रहे हैं।

स्टेट बैंक का कार्य

सार्वजनिक क्षेत्र के गुण दोषों के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि आज सवेरे मैं इस पर बोल चुकी हूं। परन्तु अनेक माननीय सदस्यों ने इस मामले को उठाया है इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि बैंकिंग के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का काम गर्व के योग्य है। मेरे माननीय मित्र श्री बाबूभाई चिनाई यहां हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से स्टेट बैंक के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। मेरी समझ में 1956 से लेकर अब तक छोटे उद्योगों को ऋण देने में इसने बड़ी सूझ और साहस से काम लिया है। 1968 के अन्त तक स्टेट बैंक और इसके सम्बद्ध बैंकों ने छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिए 162 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

रुपये भेजने में भी स्टेट बैंक ने बहुत मदद की है। सन् 1969 में ही देश भर में फैले हुए सहकारी बैंकों के लिए इसके द्वारा करीब 700 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। शुरू से ही स्टेट बैंक ने छोटे कस्बों और गाँवों में बैंक की शाखाएं खोलने में विशेष ध्यान दिया है। स्टेट बैंक और उसके सम्बद्ध बैंकों की 70 प्रतिशत से अधिक शाखाएं 25,000 जनसंख्या से कम के कस्बों में खुली हैं। उसकी करीब 60 प्रतिशत शाखाएं ऐसे छोटे स्थानों में हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नई सुविधाएं देने में भी स्टेट बैंक आगे रहा है—जैसे यात्री चैक, ऋण का तबादला, छोटे उद्योगों के लिए किश्तों में ऋण, एक आदमी वाले दफ्तर और मिस्त्रियों, परिवहन चालकों और फुटकर रोजगारियों की सहायता की योजनाएं। स्टेट बैंक ने ये सब नए काम बैंकिंग और व्यापार के सिद्धान्तों का उल्लंघन किए बिना किए हैं। जमा रकम के मामले में भी दूसरे बैंकों के मुकाबले उसका काम ज्यादा अच्छा रहा है।

1968 में इसमें जमा रकम की राशि में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उसका काम दूसरे बैंकों से बेहतर रहा। श्री चिनाई ने कहा है कि 1960-68 के बीच स्टेट बैंक की जमा राशि में केवल 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि निजी अनुसूचित बैंकों की जमा राशि में 164 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका कारण क्या है ? दिसम्बर 1960 के अन्त में स्टेट बैंक के पास कुल जमा राशि 576 करोड़ थी जिसमें से पी-एल० 480 की जमा राशि 241 करोड़ थी। यह राशि अगले दो तीन वर्षों में रिजर्व बैंक में जमा कर दी गई इसलिए यदि हम इन राशियों को हटा दें तो दिसम्बर 1968 के अन्त तक स्टेट बैंक में जमा राशि, 576—241 अर्थात् 335 करोड़ से बढ़कर 1061 करोड़ हो गई। इस वृद्धि की दर 200 प्रतिशत होती है। इससे यह जाहिर हो जाता है कि स्टेट बैंक के कामकाज में सरकार ने राजनीतिक या अन्य कारणों से कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। यह इस सदन को और देश की जनता को भी आश्वासन है कि जिन बैंकों को हमने ले लिया है वे सरकार के विभाग की तरह नहीं बल्कि अच्छे व्यवसायी संस्थानों की तरह काम करेंगे।

ऋण किस को

मैं एक बात बहुत जोर देकर कहना चाहती हूं कि व्यवसाय का यह मतलब नहीं है कि ऋण केवल उन लोगों को दिया जाए जो जायदाद की जमानत दे सकें और उन लोगों को न दिया जाए जिनकी योजनाएं ऋण पाने के योग्य हैं। मेरी समझ में व्यक्ति की साख या आर्थिक स्थिति के बजाय उद्देश्य को देखना चाहिए अर्थात् यह देखना चाहिए कि जिस काम में रुपया लगाया जा रहा है, वह लाभकर है या नहीं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिन कामों से उत्पादन बढ़े और लोगों को रोजगार मिले उनके लिए ऋण देना चाहिए। सट्टेबाजी और ऐसे ही कामों के लिए नहीं। आज हमारे बैंकों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वह देख सकें कि जिन कामों के लिए ऋण मांगा जा रहा है, वे सफल हो सकेंगे या नहीं। इसलिए सरकार कर्मचारियों को उद्योग या व्यवसाय की योजनाओं को परखने की शिक्षा देने का प्रबन्ध करेगी। चौदहों बैंकों के साधनों को मिला कर कर्मचारियों को इस प्रकार शिक्षा देने का कार्यक्रम बनाया जा सकेगा।

मैंने कई बार कहा है और फिर भी कहना चाहती हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का यह मतलब नहीं है कि मौजूदा उद्योगों को वास्तविक उत्पादन के कामों के लिए ऋण न मिलेगा। मगर हम यह भी जानते हैं कि कुछ संस्थान ऐसे हैं जो अपने साधनों को तो दूसरे कारोबार पर कब्जा करने और शेयरों को हथियाने में लगाते हैं और नये उद्योग खोलने के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं। मुझे विश्वास है कि सदन भी इससे सहमत होगा कि इन प्रवृत्तियों को रोकना चाहिए।

मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सारे देश में ऋणों का उचित बटवारा हो सकेगा। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे देश के बहुत-से भाग इसलिए नहीं पिछड़े हुए हैं कि उनमें प्राकृतिक साधनों की कमी है, बल्कि उनके पिछड़ेपन के कुछ और कारण हैं। हमें इसका प्रबन्ध करना चाहिए कि रुपया या ऋण की कमी से उनका पिछड़ापन बना न रहे। राष्ट्रीयकरण के बाद पिछड़े हुए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। उद्योगों के विकास के लिए रुपया जुटाने वाले संस्थानों ने हाल में यह निश्चय किया है कि वे पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देंगे और राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी इन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की उन्नति में रुपया लगाना चाहिए।

रुपया जमा कराने वालों का हित

यह अफसोस की बात है कि कुछ जिम्मेदार लोग और संसद में भी कुछ लोग रुपया जमा करने वालों के मन में सन्देह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका रुपया सुरक्षित नहीं है। मैं उनको आश्वासन देना चाहती

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हू कि रुपया जमा करने वालों के हित का ख्याल सबसे पहले रखा जाएगा और उनको विश्वास रखना चाहिए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में उनकी जमा रकम उतनी ही सुरक्षित है जितनी स्टेट बैंक या डाकखाने के बचत बैंक में।

आलोचक इस बात को भूल जाते हैं कि बहुत दिनों से हमारे देश के थोड़ा पैसा बचाने वाले लोग अपनी बचत डाकखाने में जमा कराते आए हैं। करीब 100 वर्ष से ये बचत बैंक कायम हैं और स्टेट बैंक में भी एक दशक से अधिक समय से बचत खाते काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि रुपया जमा करने वाले लोग उन सब की बात पर ध्यान नहीं देंगे, जो उनके शुभचिन्तक बनते हैं। उनकी असली शुभचिन्तक सरकार है। हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को नम्रता और कार्यकुशलता को अपना मूल मन्त्र बनाना चाहिए। सरकार पर ही नहीं राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारियों और ऊंचे अधिकारियों पर भी विशेष दायित्व आ गया है। मुझे कोई सन्देह नहीं कि ये कर्मचारी और अधिकारी सच्ची लगन से काम करेंगे और जनता की सेवा के इस मौके को हाथ से न जाने देंगे। मुझे सार्वजनिक क्षत्र के कर्मचारियों की समझदारी में पूरा विश्वास है और मुझे भरोसा है कि वे इस विश्वास को पूरा करेंगे।

मैं यह भी बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने स्वयं मेरे पास आकर मुझे अपने सहयोग का आश्वासन दिया है। मैं व्यापारी और औद्योगिक लोगों से अनुरोध करती हूं कि वे राष्ट्रीयकण को हारे दर्जे न स्वीकार करें, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की उन्नति में हाथ बटावें। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि सरकार का और उनका हित इसी में है कि आर्थिक उन्नति की गति को तेज करने में मिलकर प्रगतिशील ढंग से काम किया जाए। अभी भी स्वतन्त्र उद्योग और व्यापार के लिए बड़ा क्षेत्र खुला हुआ है इसलिए मैं आशा करती हूं कि सरकार की नीति की केवल आलोचना करने के बजाय वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और हमारी योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में सरकार का साथ देंगे।

व्यापक समर्थन

मेरी समझ में हाल के वर्षों में सरकार के किसी काम को इतना व्यापक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समर्थन नहीं मिला है जितना बैंकों के राष्ट्रीयकरण को। केवल किसान, छोटे उद्योग वाले, मजदूर संघ के लोग और कर्मचारी तथा प्रबन्धक वर्ग के लोगों ने ही इसका स्वागत नहीं किया, बल्कि और लोग भी मेरे पास इसके समर्थन के लिए आए हैं। उन्होंने इस काम के औचित्य का ही समर्थन नहीं किया है, बल्कि इसे सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति के लिए सरकार की उत्सुकता का प्रतीक माना है। जनसंघ ने दूसरे सदन में जो रुख लिया था और इस सदन में उसके रुख में जो अन्तर दिखाई पड़ा है वह इस बात का प्रमाण है अन्धविश्वास और साम्प्रदायिकता का पर्दा उनकी आंखों पर पड़ा रहने के बावजूद, उन्होंने चारों तरफ उमड़ने वाली जनभावना का अनुभव इन्हीं दो-चार दिनों में किया है।

स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा सदा से टेढ़ी रही है और एक बार फिर से इसका प्रमाण मिल गया है। मैं इस सदन से केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या किसी व्यक्ति का किसी विशेष बैंक में रुपया रखने का अधिकार, जनसाधारण के जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के अधिकार से बड़ा है जो हमारे संविधान में भी प्रतिष्ठित है। हम सबके अधिकार हैं, हम सबकी जरूरतें हैं। मगर कुछ तुलना भी तो होनी चाहिए। कुछ वर्ष पहले मैं अमेरिका गई थी। वहां मैंने महाराष्ट्र की एक कहावत का हवाला दिया था—"एक आदमी ने कहा कि मैं रोना रो रहा था कि मेरे पांव में जूते नहीं हैं मगर मैंने दूसरे आदमी को देखा जिसके पांव ही नहीं थे।" हमें देश की समस्याओं को इस दृष्टि से देखना चाहिए। हम किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहते, जब तक कि ये अधिकार बहुत अधिक दूसरे लोगों के ज्यादा न्यायोचित अधिकारों के विरुद्ध न हों। हमारे सामने यही सवाल है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि मैंने कहा था कि 95 प्रतिशत जनता ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। इसके बाद मजदूरों, किसानों, रिक्शावालों, संगतराशों आदि बहुत-सी अन्य संस्थाओं के अलावा बैंकर, सम्पादक, और रुपया जमा करने वाले आदि बौद्धिक वर्गों के भी बहुत-से लोगों ने मुझको लिखा है कि उनकी गिनती भी इसी 95 प्रतिशत में की जाए। माननीय सदस्य स्वयं इस बात का फैसला करें कि थोड़े-से आदमियों की नाराजी से अराजकता पैदा होने का डर है या हमारे देश की उस विशाल गरीब जनसंख्या की नाराजी और क्षोभ से, जिनकी गरीबी और आर्थिक कष्ट निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कम्युनिज्म का हौआ

यहां कुछ माननीय सदस्यों ने और बाहर भी बहुत से लोगों ने कम्युनिज्म का हौआ खड़ा किया है। यह भी अजीब बात है कि अमेरिका का मैकार्थीवाद जो अपने देश में मर चुका है, सात समुद्र पार करके इस देश में आ गया है। यह इस बात को प्रगट करता है कि जो लोग इस हौए को खड़ा कर रहे हैं वे सन् 1969 में भारत में जो राजनीतिक प्रवृत्तियां काम कर रही हैं उनसे कितने अपरिचित हैं। मैंने अभी एक भाषण दिया था उस पर एक आर्थिक समाचार पत्र में बड़े सनसनीदार शीर्षक दिए गए। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जो मैं वर्षों से, जब मैं कांग्रेस की अध्यक्ष थी उसके पहले से और उसके बाद से, नहीं कहती आ रही हूं। मैंने लोगों से जो बात कही थी, उसको तोड़-मरोड़ कर पेश करने का यह प्रयत्न था। अवश्य ही मैंने कहा था कि बहुत-से परिवर्तन यहां होंगे। क्या यहां कोई ऐसा आदमी है जो यह कहेगा कि हम अपने देश में परिवर्तन नहीं चाहते। फिर किस काम के लिए हम यहां बैठे हैं और सरकार किस काम के लिए है।

हम में से हरएक आदमी का, जो जिम्मेदार है और जो देश का हित चाहता है, यह कर्तव्य है कि वह प्रयत्न करे कि देश में जितनी जल्दी हो सके परिवर्तन हो। क्योंकि लोगों की अधीरता बढ़ रही है। यह पहले ही कहा जा चुका है और मैंने कहा कि हमने यह एक छोटा-सा कदम उठाया है। मैं नहीं समझती कि यह बड़ा भारी या क्रान्तिकारी कदम है। पर यह एक निश्चित दिशा में बहुत निश्चित कदम है और मैंने यह कहा है कि यदि हम इस कदम को नहीं पूरा करते और इसके बाद जो कार्रवाइयां जरूरी हैं, उनको नहीं करते तो यह कदम बेकार होगा। यही मैंने कहा है और यही मेरा विश्वास है। इस देश में बहुत-सी चीजों को बदलना है। मैं नहीं समझती कि इसका समाजवाद से कोई सम्बन्ध है। यह तो मामूली अक्ल की बात है।

इसलिए हमें होश हवाश खोकर टिटहरी की तरह समुद्र को धकेलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यहां तो समुद्र एक जनसमुद्र है, ऐसा जनसमुद्र जो राजनीतिक चेतना रखता है और जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया है और कष्ट सहे हैं और जो आज उस आजादी को वास्तविक बनाने के लिए और देश के विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कष्ट सह रहे हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जनता में जोश

आज जनता में अपनी हालत सुधारने के लिये जो जोश उमड़ रहा है उसको रोकना न तो मेरी शक्ति में है न विरोधी दल के माननीय सदस्यों की शक्ति में। देश में इस छोटे से कदम से जो गहरा प्रभाव पड़ा है, उसकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। मैं यह नहीं सोचती कि कोई भी आदमी, नासमझ से नासमझ या गरीब से गरीब यह सोचता है कि इससे एकदम उसका जीवन बदल जाएगा जैसे यह कोई जादू की छड़ी हो। वे जानते हैं कि यह बात नहीं है मगर वे यह अनुभव करते हैं कि कम से कम अब गाड़ी चल निकली है और जिस गड्ढे में हम अब तक पड़े थे उससे बाहर निकल आए हैं। कितनी दूर हम जाते हैं और कहां जाते हैं यह हमारे ऊपर है। मगर वे जरूर सोचते हैं कि जो शक्तियां हमको जकड़े हुए थीं और आगे नहीं बढ़ने देती थीं उनसे हम छूट निकले हैं। यह जोश और बदली हुई मनोवृत्ति जितनी हमारे दल में दिखलाई पड़ती है उतनी और कहीं नहीं। जो कांग्रेस-जन जनता के बीच में रहते हैं वे अनुभव करते हैं कि वर्षों पहले स्वतन्त्रता संग्राम के समय हमारे नेताओं ने जनता को जो आशाएं दिलाई थीं और जिन उद्देश्यों को उनके सामने रखा था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण उनकी पूर्ति का, एक प्रयत्न है। जनता को दिए हुए वचन पूरे करने और बदलते हुए जमाने के साथ आगे बढ़ने की दिशा में यह एक कदम है। मैं एक उद्धरण देना चाहती हूं।

> "मैं समझता हूं कि वर्षों तक भारत को ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जो शोषितों और दलितों को उस गड्ढे से निकालें जिसमें उन्हें पूंजीपतियों जमींदारों और ऊंचे कहे जाने वाले लोगों ने धकेल दिया है। अगर हम इन लोगों को इस दलदल से निकालना चाहते हैं तो भारत की राष्ट्रीय सरकार का यह आवश्यक कर्तव्य होगा कि वह अपने घर को ठीक करे और बराबर इन लोगों को ऊंचा स्थान दे और उन को उस बोझ से उबारे जिसके नीचे वे पिसे जा रहे हैं।"

यह किसी कम्युनिस्ट ने नहीं कहा है, यह महात्मा गांधी ने कहा है।

किसी माननीय सदस्य ने, मेरे ख्याल में मेरे मित्र श्री श्यामनन्दन मिश्र ने आशंका प्रकट की है कि इससे राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। राजनीति के बड़े विचित्र और अलग-अलग अर्थ हैं। बहुत दिन पहले जब मैं इंगलैंड में पढ़ती थी मैंने 'अराजनीतिक राजनीति' शब्द सुना था। इसका अर्थ यह है कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
मौजूदा स्थिति में कोई भी परिवर्तन राजनीतिक कार्य समझा जाता है। मगर कोई आदमी अगर मौजूदा स्थिति से चिपका रहे और परिवर्तन का विरोध करता रहे तो उसे अराजनीतिक माना जाता है। कुछ दिन हुए मैंने एक प्रसिद्ध गैर-कम्युनिस्ट उदार विचारों के ब्रिटिश पत्र में पढ़ा था कि किस प्रकार इस विषय में दुरंगेपन से काम लिया जाता है। प्रगतिशील कार्रवाई को किताबी या कागजी हस्तक्षेप बताया जाता है और स्थिति को बनाए रखने की दक्षिणपंथी कार्रवाई को स्वतंत्र विचार के व्यक्ति की समझदारी का नाम दिया जाता है। इसी प्रकार यह दुरंगी और भ्रान्त विचारधारा हमारे देश में भी पाई जाती है।

भविष्य का कार्यक्रम

मैंने पहले कहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे एक बड़े कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। अखबारों में जो सनसनीदार शीर्षक निकल रहे हैं उनके कारण मैं कहना चाहती हूं कि हमारे भविष्य के कार्यक्रम के बारे में कोई रहस्य की या चौंका देने वाली बात नहीं है। हमारी नीति और हमारे कार्यक्रम हमेशा से जनता के सामने स्पष्ट रहे हैं। हमारी पार्टी जिन समाजवादी उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है और जिन्हें हमने संसद के सामने पेश किया है उनका समर्थन संसद कर चुकी है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण उसी उद्देश्य से किया गया है। हमारे कार्यक्रम के और अंग—हमारी योजनाओं में और हमारी आर्थिक नीति में जिन्हें हमारे महान दल ने स्वीकार किया है, शामिल किए गए हैं। अभी हाल में बंगलौर में हमारे दल ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव में उन सबको निर्दिष्ट किया है। हमारे कार्यक्रम के ये ही अंग हैं, उन्हें गहराई से अध्ययन करने और पूरा करने की जरूरत है।

आज हमने एक कदम उठाया है। हमें देखना है कि इस पर ठीक ढंग से अमल किया जाता है। मगर हम उन अन्य कार्यक्रमों पर भी ध्यान देंगे जिन्हें हमारी पार्टी ने स्वीकार किया है। इस समय हमें एक भावना की जरूरत है कि हमें जरूरी काम करना है, आगे बढ़ना है, सेवा करनी है। इस अवसर पर हमें इसी भावना और लगन से काम करना है। काफी दिनों के बाद हमने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस कार्यक्रम को इतने निश्चय से और दो दलों को छोड़कर बाकी सब राजनीतिक दलों के और देश के समर्थन से उठाया है। इस प्रकार हम सहयोगपूर्वक देश को इस दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्न करेंगे, एकदम से नहीं, मगर एक-एक कदम करके हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हम इस दलदल से निकलें और अच्छे और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ें।

आगे के काम

एक दफा फिर हम सब इस ऐतिहासिक स्थान पर जमा हैं। यह 15 अगस्त हमारे इतिहास का एक मील होता है और हमको मौका मिलता है कि हम पीछे मुड़कर अपने इतिहास को देखें, अपनी प्राप्तियों पर, अपनी कमियों पर निगाह डालें और साथ ही साथ आगे भी देखें कि किस तरफ हमको जाना हैं, किस तरह हम जा रहे हैं।

हम सबको मालूम है कि इन वर्षों में इस देश में क्या-क्या हुआ। हमारे देहातों में क्या काम हुआ, कृषि का क्या काम हुआ, इन वर्षों में कितनी उन्नति हुई। अनाज की पैदावार बढ़ी। हमने कोशिश की कि जो सबसे दबे हमारे किसान थे, उनको कुछ राहत दें, जमींदारी को हटाकर लेकिन हमें मालूम है कि यह सब करते हुए भी बहुत कमियां आज हैं। उद्योग के क्षेत्र में केवल उन्नति ही नहीं हुई, लेकिन एक मायनों में सारे उद्योग आजादी के बाद ही स्थापित हुए। उसमें भी हमारी कोशिश रही कि बड़े-बड़े उद्योग

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 1969) के अवसर पर लाल किले से दिए भाषण से।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकारी क्षेत्र में रखें, एकाधिकार को बन्द करें, लेकिन हमें मालूम है कि कुछ हद तक हुआ, किन्तु वह जैसा हम सोचते थे, वैसा पूरा न हो पाया। सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योग आरम्भ हुए, चालू हो रहे हैं और कई जगह पर कई आवाजें उनकी आलोचना भी करती हैं, लेकिन अगर कोई ईमानदारी से देखे तो मालूम होगा कि अभी तक ये उद्योग बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं।

जो हमारे किसान भाई हैं, वे तो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको इससे क्या लाभ पहुंचा है। पानी की, बिजली की और बहुत-सी आवश्यकताएं पूरी हुई हैं लेकिन हमको यह भी मालूम है कि कुछ थोड़े-से हैं, जो जैसा चलना चाहिए, वैसे नहीं चल रहे हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश में हैं कि उनमें भी सुधार लाएं। क्योंकि मैं समझती हूं कि यह सरकारी चीज नहीं, बल्कि जनता की जायदाद है और जितनी जल्दी इनमें मुनाफा होगा, जितना ये अच्छी तरह से चलेंगे, उतना ही लाभ हमारी जनता को पहुंचेगा। हरेक दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बीच में जब संकट आया—चाहे सीमा पर युद्ध का संकट आया, चाहे देश के भीतर सूखे का संकट आया, चाहे जो दंगे होते हैं, और तरह की गड़बड़ें होती हैं— उन सबसे देश को हानि जरूर हुई, लेकिन मैं मानती हूं कि उससे हमारा अनुभव बढ़ा, हमने कुछ सीखा और हमने कदम और जोरों से और मजबूती से आगे बढ़ाया।

लेकिन मैं यह भी कह सकती हूं कि उस रास्ते में हम चले। अभी मैंने कुछ शहरों का नाम लिया और बताया कि एक-एक शहर में जो प्रस्ताव पास हुआ उससे हम समाजवाद के रास्ते पर और आगे बढ़ और वह रास्ता भारत की जनता का चुना हुआ, भारत के लोकतन्त्र का चुना हुआ रास्ता था और है। और उसी रास्ते का एक कदम अभी हाल में लिया गया। आप सबको मालूम है कि वह क्या है। वह था, कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मुझे मालूम है कि इस कदम का कितना बड़ा स्वागत जनता में हुआ, मुझे मालूम है कि कितने छोटे और बड़े लोग मेरे पास आए या मुझे लिखा या संदेश भेजा, मुझे बताने के लिए कि यह कदम एक ठीक कदम है। मेरे पास रिक्शा वाले आए, तांगा वाले आए, पत्थर तोड़ने वाले आए। ये सब लोग आज आजाद भारत के शहरों में सबसे अधिक कठिनाई आज भी सहते हैं, लेकिन इस नए उजाले में उनकी हमें इन सब आशाओं को उठाना है। यह नहीं कि एकदम उनकी बहुत-सी मदद हो जाएगी, लेकिन नए रास्ते दिखाकर शायद वे भी अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकें और यह भी हो सकता है कि अपने पेशों को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बदलने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया बदल रही है। बहुत-सी पुरानी चीजें आहिस्ता-आहिस्ता बदलती जा रही हैं। चाहे वे हमको अच्छी लगें या बुरी, ये सब रोजगार जो हैं, इसमें हमको सबकी मदद करनी है और इस तरह का मौका हमें सब लोगों को देना है। इस तरह से बहुत से काम हो सकते हैं, जिसे समाज, सरकार, पड़ोसी, सबको मिलकर इन लोगों की मदद करनी है और उनको एक नया जीवन देना है

प्रगति के लिए अपेक्षित शान्ति

हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत दफा हिंसा होती है या हमारे बीच में जो अल्पसंख्यक जातियां हैं, उनके विरुद्ध कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाइयां होती हैं, कुछ शक पैदा होते हैं, कुछ गुस्सा बढ़ता है, जिससे हमारी एकता भंग होती है। जिससे हमारे देश की शांति भंग होती है और हमको मालूम है कि शांति भंग होगी, तो पैदावार नहीं बढ़ सकती है। हरेक वर्ग के सामने कुछ परेशानियां और कुछ कठिनाइयां हैं, और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे ही नई कठिनाइयां आती हैं और उनका हमें सामना करना होगा। इसके लिए हमें सारी ताकत चाहिए और वह ताकत तभी मिल सकती है, जब हम सब मिलकर एक-दूसरे की परेशानियों का सामना कर सकें।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो कुछ ऐसी हवा उड़ाई गई, जैसे किसी वर्ग के खिलाफ यह काम हो रहा है। मैं साफ कह देना चाहती हूं कि हम किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सब मिलकर चलें। लेकिन जो लोग हमारे देश में थोड़े-से धनी हैं या पूंजीपति हैं, उनसे मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि यह जो कदम हम उठा रहे हैं, यह उनके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जनता के हक में है और जो चीज जनता के हक में हैं, वह उनके हक में भी है। इस दृष्टि से उनको इस कदम और जो भी देश में हुआ, उसको देखना चाहिए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्रान्ति अभी पूरी नहीं हुई

हमारे देश में बड़ी भारी क्रान्ति आई, जब महात्मा गांधी ने आजादी का आन्दोलन शुरू किया लेकिन उसे नम्रता से उन्होंने किया और सब को मिलाकर किया। हमारे देश को हिला दिया और एक बाहरी राज्य को बदलकर अपने देश में एक स्वतंत्र राज्य को जमाया। यह जो क्रांति हुई, उसका अभी खात्मा नहीं हुआ, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में देश को और समाज को हर वक्त बदलते रहना है।

मुझे दुख है कि कुछ आवाजें उठीं, जो कहने लगीं कि जो कदम हमने उठाए, वे शायद कुछ बाहरी शक्ति या बाहरी देश या बाहर की विचारधारा की वजह से हम कर रहे हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि यह चीज हम यहां की जनता और जो हमारे देश में लोकतन्त्र है, उसमें सबको मिलकर करनी है। मुझे मालूम है कि भारत की जनता के दिल में लोकतन्त्र की भावना जमी हुई है। वे कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जिससे किसी तरह भी हानि हो या किसी तरह से हमारी स्वतन्त्रता पर आंच आए, चाहे वह हमारी विचारधारा द्वारा हो या चाहे बाहरी हमले के द्वारा हो।

हम जिस भी रास्ते पर जा रहे हैं, वह भारत का रास्ता है, भारत के इतिहास से, भारत की संस्कृति से निकला हुआ रास्ता है। लेकिन यह सब है कि हर कदम पर वह रास्ता एक नया रास्ता भी बन जाता है। हमने इतनी उन्नति की, तब भी क्या वजह है कि कुछ लोगों के मन में अशान्ति है, असंतोष है। इसी चीज की कमी रही। केवल उन्नति या विकास की कमी नहीं है, क्योंकि मनुष्य को किसी और चीज की भी जरूरत होती है। कभी-कभी मनुष्य के जीवन में समय आता है जब उसके दिल में उसके भीतर से एक क्रान्ति उभर आती है। जब वह अपनी आत्मा को और गहराई से पहचान सकता है। जब वह परिस्थितियों को और सफाई से देख सकता है, ऐसा ही समय भारत में आज आया है और एक नया दरवाजा खुला है। जिन लोगों को बंद में रहने की आदत हो गई थी, वे उस ठण्डी और ताजी हवा से कुछ चिंतित हुए हैं, लेकिन बहुत-से ऐसे हैं जो घुटन होने से परेशान हो गए थे, उनको इस तेजी से सांस लेने से नई शक्ति मिली और मिलेगी।

बाईस वर्ष हुए जब रात के अन्धेरे में भारत स्वतन्त्रता में जागा। उस समय पंडित जी ने कहा था कि हम अपने भविष्य से भेंट करने को निकल पड़े

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हैं। आज फिर एक वैसे ही मोड़ पर हम पहुंचे हैं, क्योंकि भविष्य एक सीमित चीज नहीं है, भविष्य तो सामने खुला है। कल का भविष्य आज वर्तमान है। और यह रास्ता हमारे सामने खुल जाता है। तो हमको इसका सामना करना है।

आपके सामने खड़े होकर मैं आपको एक आश्वासन देना चाहती हूं कि मैं चाहे जहां भी रहूं, चाहे जो काम कर रही हूं, मेरे सामने जो सबसे महत्व का काम है, वह एक है—और वह जनता का, आप सब भाइयों और बहनों का हित है। और इस कार्य में एक बात मुझे आपके सामने रखनी है। गांधीजी ने हमको एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर कभी कोई कदम लेते हुए मन में शंका हो, तो जिस सबसे गरीब और कमजोर मनुष्य को जानते हो, उसकी ओर ध्यान करो। अगर उस कदम से उस मनुष्य पर अच्छा असर पड़ता है, कुछ लाभ मिलता है, तब वह कदम ठीक कदम है, तब उस रास्ते पर चलोगे तो शंकाएं दूर हो जाएंगी ओर रास्ता साफ हो जाएगा। इस भावना को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूं।

नए मोड़ पर

आज हमने एक नया मोड़ लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवान चाहे वे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे हमारी फौज में हों, चाहे हमारे शहरों में रहनेवाले हों, या देहात में रहने वाले हों, वे सब इस नए रास्ते पर चलकर एक नया जोश अपने देश में लाएंगे, एक नई कुरबानी की भावना लाएंगे। यह समय है, जब हम सबको एक ही तरफ निगाह डालनी है और वह है भारत की जनता, भारत के गरीब। अगर हम उनको उठा सकते हैं, तो हम सब उठ सकते हैं। अगर हम में शक्ति है और शक्ति के साथ करुणा है, शक्ति के साथ दूसरे की परिस्थितियों की जानकारी है, दूसरों की स्थिति पर सहानुभूति है, तब हम सब मिलकर इन बड़े-बड़े कामों को कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता इसमें सदा एक रहेगी।

मेरे सामने सब बच्चे यहां बैठे हैं, वे भविष्य के नागरिक हैं, जिनसे हम बहुत कुछ आशा रखते हैं, इनको हम चाहते हैं कि बराबर के मौके मिलें और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
आज जो ऊंच-नीच है, आज जो एक वर्ग और दूसरे वर्ग में अन्तर है, उसको हम कम करना चाहते हैं। हमें यह अन्तर कम करना है। न खाली यह कि उसके बीच में, जिसके बीच में हमने किया है और जो आगे भी करना है, बल्कि जो हम बने हैं और जो हम बनना चाहते हैं, उसका अन्तर भी हमको खत्म करना है।

बैंकों की नई भूमिका

आप लोगों ने जिस कार्य कुशलता से इन हालात में काम सम्हाला है उसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगी। मेरे विचार में भविष्य के लिए भी इससे अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि भविष्य में ऐसे कितने ही अवसर आएंगे जबकि हमें परस्पर मिलकर कार्य करना होगा और एक ही मार्ग निर्धारित करना होगा, जिस दिशा में हम भारतीय बैंक प्रणाली और अपनी ऋण नीतियों को ले जाना चाहते हैं और इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के साथ-साथ हम भारतीय जनता की सेवा कर सकें।

हर बैंक के कस्टोडियन को पूरा-पूरा अधिकार दिया गया है जिससे वे विभिन्न समस्याओं से निपट सकें और मुझे आशा है कि अपने काम के दौरान कस्टोडियन इन अधिकारों का प्रयोग करेंगे। ऐसे मामलों में जिनमें निर्णय लेने के लिए वे पूर्णतः सक्षम हों, उन्हें अन्य दिशा-निर्देश प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

बैंकर क्लब दिल्ली में भाषण 28 अगस्त 1969।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मैंने सुना है कि बैंक व्यवसायियों और व्यापार एवं उद्योग के कुछ वर्ग में असुरक्षा की भावना है। स्पष्ट ही मैं इस असुरक्षा की भावना की कोई जरूरत नहीं समझती। यों तो कुछ हद तक हम सभी असुरक्षित हैं, हम नहीं जानते कि कब भूचाल या बवंडर आएगा और इस संसार का अन्त कब हो जाए या ऐसी ही दुर्घटना कब और कहां उठ खड़ी हो ? लेकिन ऐसी भयंकर बरबादियों को छोड़ कर असुरक्षा की भावना के लिए और कोई कारण नहीं है यह बात मैं अपने प्रारंभिक रेडियो प्रसारण और तत्पश्चात अनेक भाषणों में स्पष्ट कर चुकी हूं। समस्त प्रणाली को खंड-खंड करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हम तो केवल दिशा निर्देश करना चाहते हैं क्योंकि मेरी राय में इसकी काफी समय से नितांत आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं है कि बैंकों में काम ठीक-ठाक न चल रहा हो। वे ठीक तरह से काम कर रहे थे, मगर उनका दृष्टिकोण कुछ सीमित हो गया था और वे देश की आवश्यकताओं से तनिक हट गए थे जहां कि मजबूत अर्थव्यवस्था जरूरी है वहां ज्यादा उत्पादन भी जरूरी है और इनमें से कोई भी एक अकेले ही संभव नहीं हो सकता। अगर सामाजिक गड़बड़ी उत्पन्न हो, क्योंकि इससे सबको खतरा है। असमानता के कारण अथवा हमारे जनता के कई वर्गों में न्याय न मिल पाने की भावना के कारण हमारे देश में सामाजिक तनाव बढ़ रहा था। अतः कोई ऐसा कदम उठाया जाए जो इस सामाजिक तनाव को दूर कर सके वही कदम हम सबके लिए स्थिरता और सुरक्षा का कदम है। अतः मैं आशा करती हूं कि आप अपने को अधिक असुरक्षित नहीं समझेंगे और हमें आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा।

अपने आप में ही लक्ष्य नहीं

अब जैसा कि मैं कई बार कह चुकी हूं, राष्ट्रीयकरण स्वयम् अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। संसद में और बाहर भी मैं कई अवसरों पर इस बात पर प्रकाश डाल चुकी हूं कि किन उद्देश्यों के लिए यह किया गया। लेकिन मैं विचार करना चाहूंगी कि किस प्रकार सफलतापूर्वक इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। मैं चाहूंगी कि प्रत्येक बैंक के पास ऐसा करने के लिए अपनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजना हो। आप सबको पता है कि चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने हमारी जनता के हृदय में अमित आशाएं उत्पन्न की हैं। वास्तव में प्रथम स्वतन्त्रता-दिवस के बाद शायद ऐसा उत्साह कभी देखने में नहीं आया। मैंने यह भी बताया है कि संभवतः उनकी सभी आशाएं पूरी नहीं हो सकतीं फिर भी उनमें जोश और उल्लास की भावना है; जाहिर है कि हम उनकी आशाओं को पूर्णतः पूरी नहीं कर सकते लेकिन उसका एक छोटा भाग पूरा करने के लिए हमें अथक प्रयत्न करना चाहिए।

हमारी ऋण नीतियों का पुनर्नवीनीकरण इन्हीं कुछ आशाओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है। हमारे बैंक जितनी और अधिक अतिरिक्त जमा-धनराशि एकत्रित कर सकें, वहां तक हमें उनकी आशाओं को पूरा करना ही चाहिए। यह काम अत्यन्त महत्वपूर्ण है, और इस मोर्चे पर जरा-सी असफलता, बैंक की कुशलता पर प्रभाव डालेगी, जो कि एक उन्नतोन्मुख अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित है। प्रत्येक बैंक को इस दिशा में पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य के साथ जुट जाना चाहिए। अधिक जमा धनराशि प्राप्त कर पाने के लिए बैंकों को संस्थात्मक आधार पर मजबूत होना चाहिए। उसके लिए खासतौर से उसकी अधिक से अधिक शाखाए खोलना आवश्यक है जो कि नियत समय में अधिक विस्तार के साथ खोली जानी चाहिएं।

अवसर भी, चुनौती भी

सक्रिय और नए रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए बैंक व्यवसाइयों के लिए बैंक राष्ट्रीयकरण अवसर भी है, चुनौती भी है, खासतौर से ग्रामीण बैंक-व्यवस्था के लिए नए-नए तरीकों और काम करने के नए ढंग की जरूरत पड़ेगी। परम्परागत तरीकों और रूढ़िवादी बैंक व्यवस्था मात्र से काम नहीं चलेगा यदि इस कृषि क्रांति में बैंकों को विकसित होना और आगे बढ़ना है; और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में दिनोंदिन बढ़ने वाली आमदनी से बैंकों को लाभान्वित होना है। ग्रामीण क्षेत्र में बचत एकत्रित कराने के लिए आप को काफी परिश्रम करना पड़ेगा; और किसानों के लिए उपयुक्त सेवाएं शुरू

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करनी होंगी जिससे वे अधिक बाधाएं और अपनी बचत का बड़ा भाग आपके पास जमा कराएं।

कर्ज देने के मामलों में भी नए विचार जरूरी हैं। प्रतिभूति की आवश्यकताओं के बारे में आपको नए ढंग से विचार करना होगा। जाहिर है कि समानान्तर प्रतिभूति मांगने के परम्परागत ढंग अथवा जमीन की मिल्कियत के कागजात मांगने से तो काम नहीं चलेगा। अपने करोड़ों किसानों और काश्तकारों के लिए भी ऐसे नए तरीके निकालने पड़ेंगे। इस सम्बंध में हमें यह विचार करना होगा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं में कैसे कोई कड़ी बांधी जाए जो मजबूत अर्थव्यवस्था के सिद्धान्तों पर आधारित हो। बैंक व्यवसायी को किसान भाइयों का एक मित्र, मार्ग निर्देशक और विचारक होना है जो उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करे, ऋण की देखभाल करे और उसके कच्चे माल के भंडार करने और विक्रय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करे।

हमारे कुछ सक्रिय बैंक व्यवसायियों ने स्वयमेव विभिन्न प्रकार की भूमियों में रासायनिक खाद के परीक्षण करने का तरीका अपना लिया है। उन्होंने नए संकर बीजों को प्रचारित किया है, मिट्टी के परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और उनके लिए आर्थिक आयोजन किया है, फार्मों के आंकड़े एकत्र कर आर्थिक दृष्टि से उनका विश्लेषण किया है, दवा छिड़कने की सेवाओं की स्थापना की है और उत्पादक एवं काया पलट कर देनेवाली गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है। परिस्थितियों की मांग को देखते हुए दृष्टिकोण अपनाने का भी कोई भी बैंक व्यवसायी कृषि में सफल नहीं हो सकता। केवल वह बैंक व्यवसायी ही सफल हो सकता है। जो एक बैंक व्यवसायी से अधिक कुछ और भी है। मुझे विश्वास है कि आप इस चुनौती का सामना करेंगे।

जनता के हित साधन के लिए ऋण

मैंने खेती के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की है क्योंकि हमारे आर्थिक विकास में खेती का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योगों को ऋण देने के लिए चाहे वे छोटे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हों या बड़े — कम सजग नहीं। उद्योगपतियों को भी सजग और सतर्क रहना होगा। किस काम के लिए ऋण लिया जा रहा है, उसकी योग्यता पर ही जोर दिया जाना चाहिए। बैंकों के पास हमारी योजनाओं के लिए टेकनीकी और आर्थिक सूझ-बूझ होनी चाहिए। उन्हें एकदम आधुनिक तौर तरीकों से युक्त होना चाहिए और बाजार और आयोजना सम्बंधी सर्वेक्षण करते रहना चाहिए। उनमें आधुनिक व्यवस्था एवं तकनीक होनी चाहिए। संक्षेप में, उन में एक सक्रिय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। और आर्थिक सहायता देने के लिए तत्पर होना चाहिए।

मैं जानती हूं कि इन समस्याओं के हल के लिए अच्छे ढंग की व्यवस्था दरकार होगी। अतः इस काम के लिए हमें अपेक्षित प्रशिक्षण सुविधाएं जुटानी होंगी। जो कि हमारी जरूरतों के अनुसार ठीक बैठें। कई आलोचकों ने यह भय प्रकट किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में विनम्रता एवं कार्यकुशलता कम हो जाएगी; लेकिन मुझे विश्वास है कि यह भय बेबुनियाद साबित होंगे। बैंक कर्मचारियों ने बड़े जोश के साथ बैंक राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया है और उन पर जिम्मेवारी है कि अच्छी सेवा करने के सुयश को न केवल कायम रखेंगे बल्कि उसमें और भी वृद्धि करेंगे।

बैंकों से देश का हित साधन

राष्ट्रीयकरण के बाद ही काफी अरसे से मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के बड़े अधिकारियों से मिलने की सोचती रही लेकिन किसी न किसी कारण से इसे

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों के समक्ष नई दिल्ली में किया गया भाषण, 30 सितम्बर 1969।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टालना पड़ा। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सब एकात्रत हो सके हैं। हमारे राष्ट्रीय जीवन में बैंकों का जो महत्व है, उसे हम सभी जानते हैं। निजी क्षेत्र में जो बैंक काम करते रहे हैं भविष्य में भी उनका स्थान महत्व-पूर्ण रहेगा। देश को उनसे मूल्यवान सेवाओं की अपेक्षा है लेकिन आप में से जो आज यहां उपस्थित हैं उन्हें एक विशिष्ट प्रकार का दायित्व और विश्वास सौंपा गया है।

पहले भी कई अवसरों पर राष्ट्रीयकरण के बारे म मैंने कहा है और मैं समझती हूं कि आप सब ने उसे सुना है, यद्यपि कभी-कभी मेरे कथन को गलत रूप भी दिया गया। राष्ट्रीयकरण के उस पहलू पर मैं इसके अतिरिक्त और कुछ न कहूंगी कि विशेषज्ञ होने के नाते स्वयं आपका ध्यान हमारी अर्थ-प्रणाली की कमजोरियों पर जरूर गया होगा। हमारे देश के एक बड़े भाग में बैंकों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, यह भी आपके ध्यान में आया होगा।

राष्ट्रीयकरण के विरोध में यह आपत्ति उठाई गई है कि बैंकों के काम में राजनीतिक विचारों से काम लिया जाएगा। मैं नहीं समझती कि ऐसा कहते समय आलोचकों के दिमाग में क्या बात आई होगी। यह ध्यान देने वाली बात है कि कुछ समय से हमें पुराने विचार बदलने पड़े हैं। सामाजिक स्वामित्व और नियंत्रण के कारण और ऐसे ही परिवर्तन होंगे।

जीवन के किसी अन्य क्षेत्र से राजनीति को एकदम अलग कर देना बड़ा कठिन है लेकिन न केवल हमारे देश में बल्कि इंग्लैण्ड जैसे देश में भी यह एक मानी हुई रीति रही है। विशेषकर अंग्रेजी पत्र के एक वाक्य की मैंने संसद में भी चर्चा की थी कि कोई व्यक्ति जो यह चाहे कि हालात जैसे के तैसे बने रहें वह व्यक्ति अराजनैतिक समझा जाता है। यद्यपि यह उतना ही राजनैतिक है जितना कि एक व्यक्ति जो परिवर्तन चाहता है। यह दोनों ही दशाएं एक-सी राजनैतिक हैं, एक दूसरे से कम या अधिक नहीं। बैंकों का अर्थव्यवस्था के विकास से इतना सम्बन्ध है कि वे राजनैतिक स्थिति के असर से पूरी तरह मुक्त नहीं रह सकते।

हमारे देश की राजनैतिक दशा यह अपेक्षा करती है कि बैंक सम्बन्धी सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाएं और यह विकास खास करके पिछड़े इलाकों, कृषि एवं लघु उद्योग और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में हो। इसका अर्थ यह है कि संभवतः बैंक उद्योग को बड़े सामाजिक उद्देश्यों के प्रति सजग रहना चाहिए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

काम करने की स्वतंत्रता

तथाकथित राजनैतिक उद्देश्य का यदि यही अर्थ है तो इसमें राजनैतिक उद्देश्य है। लेकिन यदि वे इसका यह अर्थ समझें कि दैनिक काम में बैंक के अधिकारियों पर कोई बाहरी दबाव डाला जाएगा, जो जन कल्याण एवं आर्थिक विकास से असम्बद्ध हो तो मैं बेझिझक आपको विश्वास दिलाती हूं कि जब तक मैं इंचार्ज हूं, आपके काम में ऐसा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत आपको पूरी-पूरी आजादी रहेगी ताकि आप एक कुशल और व्यवसायिक बैंक अधिकारी के रूप में केवल अपनी ईमानदारी और व्यवसाय के नियमों के अनुसार कार्य कर सकें। हम इससे भी अनभिज्ञ नहीं कि बैंक व्यवसायियों में से कम से कम कुछ, शायद यहां उपस्थित व्यक्तियों में से भी कुछ पर, पहले अनुचित दबाव डाला गया हो और इसका कारण बड़े व्यापारी एवं बैंकों के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों में तलाश किया जा सकता है। अपने दिन प्रतिदिन के कामों में भी बैंक प्रबंधकों को टोका जाता था और यह हस्तक्षेप उन निर्देशकों द्वारा किया जाता था जो बड़े उद्योगों एवं बड़े व्यापारों से सम्बद्ध होते थे। इस प्रकार के कुप्रभावों से, जो उनके निर्णय को अवरुद्ध करता था, बैंक प्रबंधकों को राष्ट्रीयकरण ने मुक्ति दिलाई है।

जमाखाते में बढ़ोतरी

पहले हम एक दुष्चक्र में फंसे थे। अतः जब मैं कहती हूं कि हमें पुराने विचार बदलने पड़े तो इसका अर्थ होता है कि इस चक्र को तोड़ा गया। उसके लिए दो काम करने हैं—पहला, देश भर में सभी वर्गों के लोग बड़े व्यापारियों से लेकर, परेशान गृहणी तक से धन जमा कराना। इसके लिए आपको शीघ्र से शीघ्र नई शाखाएं व्यापक पैमाने पर खोलनी होंगी जो गांवों व छोटे कस्बों में हों और इस प्रकार आपको निरन्तर यह प्रयास करना होगा कि छोटे-बड़े, सम्पन्न, खेती, उद्योग, व्यापार एवं अन्य पेशों में लगे लोगों से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपना कारबार करने वाले और श्रमिक, सभी से बचत एकत्रित करें। ये जमा धनराशियां, जो कि छोटे-छोटे स्थानों के साधारण से लोगों से एकत्रित की जाएंगी, बड़े शहरों में जमा धनराशि की अपेक्षा कहीं अधिक होंगी। इन करोड़ों छोटे खातेदारों तक पहुंचना एक कठिन समस्या होगी, लेकिन राष्ट्रीयकरण में हम सबको कस कर काम तो करना ही होगा, न कि आराम।

समन्वित विस्तार

मैं समझती हूं कि कुछ दिन पहले आपने अगले कुछ मासों में शाखाओं के विस्तार के लिए जो कार्यक्रम बनाया था, उस पर आप लोग तथा रिजर्व बैंक आगे विचार कर ही रहे हैं। मुझे आशा है कि इन योजनाओं के निर्माण में आप अन्य बैंकों से समन्वय करेंगे, जिससे बैंक की शाखाओं का विस्तार शान के लिए ही न हो, बल्कि जनता को उनसे नियमित सेवा मिले और आपके बैंक को लाभ हो। छोटे-छोटे कस्बों और गांवों, खास कर अल्प विकसित इलाकों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हम इस बात को नजरन्दाज नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी आबादी गांवों में रहती है और भविष्य में भी काफी समय तक गांवों में रहेगी। आप लोगों में से कुछ से, मैंने अलग जो बात की है, उससे मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि आपके बैंक, कृषि क्षेत्र के और साथ ही नगरों के छोटे आदमियों की सेवा में उद्यत हुए हैं।

ग्रामीण लोगों से व्यवहार

आपमें से ही किसी ने आज प्रातः मुझे बताया और यह एक अच्छा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विचार है कि गांव में काम करते समय मानवीय दृष्टिकोण रखना होता है, जिससे कि वे लोग भयभीत न हों, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन मिले। इसके लिए आपको कुछ तरीके निकालने होंगे। यह तो आप ही को निश्चय करना है कि यह काम कैसे किया जाए ? कभी-कभी लम्बे-चौड़े फार्मों को भरने और हमारे बातचीत करने के ढंग से वे भयभीत हो जाते हैं। इसके लिए हमें इस वर्ग के साथ कुछ खास तरीके अपनाने होंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि इसके लिए अतिरिक्त घण्टे काम करना आवश्यक होगा। यदि किसी स्थान पर दो बैंक हैं तो वे थोड़ा अंतर रख कर खुलें जिससे खेतों में काम करने वाले किसान जो एक खास समय पर बैंक न आ सकें, इसके लाभ से वंचित न रहें।

यह बात मैं मोटे तौर से ही कह रही हूं, लेकिन इसका पूरा कार्यक्रम आपको ही तय करना है। मैं तो इसकी चर्चा केवल इसलिए कर रही हूं कि काम करने के निर्धारित तरीकों एवं ढंग से थोड़ा हटने की जरूरत है। कोई भी देश, जो आगे बढ़ेगा, अपने सोचने एवं काम करने के तरीकों में सुधार करेगा ही। मेरे विचार में, हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी कमी है। हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़े पर हमने अपना तरीका नहीं बदला। इससे आगे बढ़ने का वह प्रभाव नहीं पड़ा जो पड़ना चाहिए था।

स्पष्ट है कि अधिक धनराशि जमा कराने के लिए हमें नई-नई दिशाओं में काम करना होगा। वैसे भी विभिन्न राज्यों एवं जिलों में जमा धनराशि में काफी अंतर है। यह आप सबका प्रयास होना चाहिए कि इस दिशा में सुधार हो।

नई ऋण नीति की आवश्यकता

काफी तादाद में धनराशि जमा हो जाए तभी ऋण का काम नहीं शुरू करना चाहिए। जमा और ऋण साथ-साथ बढ़ने चाहिए। बहुत से अल्प विकसित क्षेत्रों में तो ऋण देना ही पहला कदम होगा। इससे यह आशा की जा सकती है कि इसके परिणामस्वरूप नए खाते भी यथाक्रम खुलेंगे। मार्च 1965 से मार्च 1967 तक के दो वर्षों में उधारखातों की संख्या 11.26 लाख

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से गिर कर 10.56 लाख हो गई। ऐसे समय पर जबकि बेकारों की संख्या तेजी से बढ़ रही हो, देश में मुद्रा चलन बढ़ रहा हो, बैंकों में जमा धनराशि बढ़ती रहे, यह देखने को आए कि छोटे आदमी महाजनों से बीस प्रतिशत से या अधिक ब्याज पर उधार लें, ऐसे समय बैंक के उधार खातों में गिरावट चिन्ता की बात है। इससे यह भी समझा जा सकता है कि बैंकों का धन जो कि जनता की सम्पत्ति है, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में एकत्रित होने लगा है। सामाजिक उन्नति के सभी नियमों के अनुसार, इस धन से लाभान्वित होने वालों की संख्या कहीं अधिक होनी चाहिए थी।

मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोग ऐसी योजना बना रहे हैं, जिससे सभी उत्पादन के कामों को चाहे वे कितने ही छोटे हों और उनकी आर्थिक आवश्यकताएं कितनी ही कम क्यों न हों, उधार दिया जा सके। आपके शाखा-प्रबन्धकों के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वे इन योजनाओं के अनुसार कर्ज देने को तैयार हों, जरूरत है कि इन योजनाओं का उनके क्षेत्र में उपयुक्त प्रचार किया जाए। इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रचार का तरीका, विभिन्न वर्गों और देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होगा।

यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य तथा केन्द्र सरकार को भलीभांति ज्ञात रहे कि आप लोग किस भांति जनता की सेवा कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों का खयाल है कि उनके क्षेत्र में से बैंक जितना रुपया बटोरते हैं उससे कहीं कम रुपया वहां उधार दिया जा रहा है। इस धारणा को निर्मूल सिद्ध करने के लिए, शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए और हालात को ठीक किया जाना चाहिए और सही सही तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिए।

झूठी आशा नहीं

हमें जनता से ऐसे झूठे वायदे करके, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, उनके मन में झूठी आशाएं जाग्रत नहीं करनी चाहिए। ऐसा प्रयत्न करना है जिससे सही दिशा में सहायता उपलब्ध हो। भारतीय जनता को भलीभांति जानने के कारण मुझे यथेष्ठ विश्वास है कि जब तक वे समझेंगे कि हम सही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
काम कर रहे हैं, तो वह हमारे साथ रहेंगे। जब उन्हें यह महसूस हो कि हम उनके फायदे का काम न करके किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हित में काम कर रहे हैं, तभी वह दूसरे तरीके अपनाते हैं। अतः हमारा सतत प्रयत्न यह होना चाहिए कि हम देखें कि जरूरतें क्या हैं और बदलते हालात में हम अपने तरीकों और एक सीमा तक लक्ष्यों को भी किस प्रकार बदलते रहें। यह मनोवृत्ति हमें विकसित करनी चाहिए।

मुझे आशा है कि आगामी वर्ष में आप लोग देश को बता सकेंगे कि आपने कितने अधिक लोगों को ऋण दिया है। खासतौर से कम आय वाले लोगों को जो कि वस्तुओं के उत्पादन, और विभिन्न सेवाओं में लगे हैं, उन्हें आप कितनी मदद दे पाते हैं। जैसे जैसे आपके बैंकों के प्रबन्धकों को छोटे छोटे खातेदारों से व्यवहार का अनुभव होता जाए, आपकी योजनाओं को सुधारा जाना चाहिए। सरकारी अधिकारी ऐसी योजनाएं बनाने में लगे हैं जिनके द्वारा एक सरल मगर व्यापक पैमाने पर गारंटी देने का प्रबन्ध हो सके ताकि उन क्षेत्रों का भी जो अब तक लगभग उपेक्षित ही रहे हैं छोटे छोटे कर्ज दिए जा सकें। इसमें खुदरा व्यापारी, छोटे धन्धे वाले, मामूली मरम्मत करने वाले, छोटे किसान और अपना धंधा करने वाले शामिल हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके प्रबन्धक डरें या हिचकें नहीं और छोटे ऋण देने में उत्साह लें। इस सम्बन्ध में ठोस सुझावों का हम सदा स्वागत करेंगे।

समन्वय के लिए परिषद्

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप लोग विचार विनिमय और गतिविधि में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक परिषद् बनाना चाहते हैं। ऐसे सभी प्रयत्नों में आपको रिजर्व बैंक तथा सरकार का सहयोग उपलब्ध होगा। अगर ठीक ढंग से काम किया गया तो इस परिषद् द्वारा कई तरह के काम मिलजुल कर किए जा सकेंगे। उदाहरण के लिए—सभी वर्गों के लोगों को बचत करने की प्रेरणा देना, देश भर में छोटे बड़े उद्योग-धन्धों को ऋण मिल रहा है या नहीं इसका ध्यान रखना और उचित उपाय करना, ऋण देने में क्या सावधानी बरती जाए, भर्ती और प्रशिक्षण के अच्छे उपाय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
करना और यथासम्भव इसके खर्च में हिस्सा बटाना तथा कार्य कुशलता को कम किए बिना प्रशासनिक व्यय में कटौती करना। आपको यह भी विचार करना है कि आपके कागज व फार्म तथा विधियां किस प्रकार और कहां तक एक जैसी हो सकती हैं। किस प्रकार आपके बैंकों का काम और मुनाफा बढ़ सकता है और बैंक सेवाओं में सुधार किया जा सकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। आपको ऐसे तरीके भी छोड़ने होंगे जिनसे छोटे बैंकों और सहकारी बैंकों को अनुचित हानि पहुंचती हो क्योंकि वे अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे इस विशाल देश में सबके लिए काम करने की गुंजाइश है।

राष्ट्रीय बैंकों के सबसे बड़े प्रबन्धकों को ऐसा प्रयत्न करना होगा जिससे उन्हें कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलता रहे। दुर्भाग्यवश बैंकों में प्रबन्धक कर्मचारी-सम्बन्ध सन्तोषजनक नहीं रहे हैं।

उत्पादकों की सहायता

बैंकिंग कम्पनीज़ (एक्वजीशन एंड ट्रांसफर आफ अन्डरटेकिंग्स) एक्ट की धारा 13 में उल्लखित योजना तैयार की जा रही है। सरकारी अधिकारी रिज़र्व बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रमुख अधिकारियों से सलाह कर रहे हैं। इसमें आप लोग जो रचनात्मक सुझाव देंगे, उन पर विचार किया जाएगा। सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि किस प्रकार सरकारी खजानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के खातों, आदि का काम चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी दिया जाए।

19 जुलाई के बाद के सप्ताहों में कुछ क्षेत्रों में यह अफवाह उड़ाई गई कि चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पादक उद्योगों को मिलने वाले ऋणों में कमी आ जाएगी। यह बात एकदम गलत थी और मुझे विश्वास है आप सब इसे जानते हैं। समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में वृद्धि होनी ही चाहिए। अन्यथा देश की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ हो जाती है और बड़े पैमाने पर बेकारी फैलने लगती है। आपको मध्यम दर्जे के और बड़े उत्पादक उद्योगों की सहायता करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
चाहिए। फिर भी कृपया स्मरण रखें कि भारत में बैंकों ने ऋण देते समय यह खयाल नहीं रखा है कि उसका उपयोग वास्तविक उत्पादन के लिए होगा या किसी और काम के लिए। आप लोगों को इस विषय में अधिक सजग रहना चाहिए जिससे बहुत बड़े उद्योग या व्यापारों को उससे अधिक ऋण न दिया जाए, जितना उत्पादन की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में उचित सलाह रिजर्व बैंक से मिल सकती है।

सजग रहने की आवश्यकता

शेयरों और माल पर ऋण देते समय भी आपको ऐसे ही सजग रहना हैं। ताकि ऐसा न हो कि बैंक के पैसे से असामाजिक तत्वों के लाभार्थ, शेयरों अथवा माल की जमाखोरी या सट्टेबाजी हो। इसके लिए उपायों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है परन्तु वर्तमान में आप लोग स्वयं ही रिज़र्व बैंक की सलाह से विचार करें। मियादी ऋण देने वाले अधिकांश संस्थान, जो उद्योग और कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं। और अब तो आप में से 14 सदस्य भी इसी क्षेत्र में आ गए हैं इस से आपके कार्य एवं कार्य की विधियों में समन्वय स्थापित करने का बड़ा अवसर मिलेगा। आप राज्य के संस्थानों से मियादी ऋण के बारे में मेल रख सकेंगे ताकि थोड़ी और लम्बी अवधि के विकास की जरूरतों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जा सके। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं, आपके लिए राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों से सम्पर्क बनाना उपयोगी रहेगा जिससे कि वे सरकारें आपकी गतिविधियों से अवगत रहें और जनता के लाभ की अपनी योजनाओं को भलीभांति बना सकें, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी नियम के विरुद्ध काम न करना पड़े या अनावश्यक जोखिम न उठानी पड़े। स्पष्ट है कि इसका अर्थ यह होगा कि सरकारी योजनाओं की आपको समीक्षा करनी पड़ेगी और सरकारों को यह सलाह देनी होगी कि उन्हें अपने और जनहित में किस तरह सावधानी बरतनी है। इससे सरकारी गारण्टी पर आश्रित होने की आपकी आदत भी छूटेगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विद्यार्थियों को सहायता

देश की नई पीढ़ी के मन में जो वर्तमान तनाव है उससे और उसके कारणों से आप परिचित होंगे। स्थापित व्यवस्था के प्रति विद्यार्थी समाज के दिमाग में जो शिकायतें हैं, हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि आप में से जो कुछ लोग विद्यार्थियों को आवश्यक सहायता देने की योजनाएं चला रहे हैं। इन योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। आप और अन्य लोग जो व्यापार, उद्योग एवं अर्थव्यवस्था के अनुभवी हैं वे भी विद्यार्थी समाज से निकट सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। आप या आपके उच्च अधिकारी इन नवयुवकों तथा जनता के अन्य वर्गों के साथ यदाकदा मिलते जुलते रह सकते हैं।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप में से कुछ लोग जनता और ग्राहकों से सम्पर्क करते समय हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करने लगे हैं। मेरे विचार में ऐसा करना जरूरी है। इससे भाषा-समस्या के सुलझाने में सहायता मिलेगी।

भय की जरूरत नहीं

मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक को जबरदस्ती दूसरे बैंक में मिलाने या ठीक से काम करने वाले किसी बैंक की व्यवस्था को पलटने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। यदि अच्छे ढंग से काम चलाने के लिए ढांचे में कोई परिवर्तन आवश्यक समझा गया तो यह विचार विमर्श और समन्वय के द्वारा ही होगा।

कुछ छोटे बैंकों ने यह भय प्रकट किया कि बड़े बैंकों के मुकाबले उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। मुझे विश्वास है कि सुनी जाएगी। राष्ट्रीयकरण के बाद अज्ञानवश कुछ क्षेत्रों में जो गलतफहमी पैदा हुई, वह अब दूर हो रही है। मैं समझती हूं कि यह शीघ्र ही एक दम समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंक, रिज़र्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में, देश अपनी राय मुख्यतः यह देख कर बनाएगा कि वे जनता को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कितनी कोशिश कर पाते हैं। मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारा सबका लक्ष्य यह है कि बैंक व्यवसायी को सब लोग कुशल सलाहकार और समाज का मित्र समझें न कि समाज के वर्गविशेष का साथी।

——

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

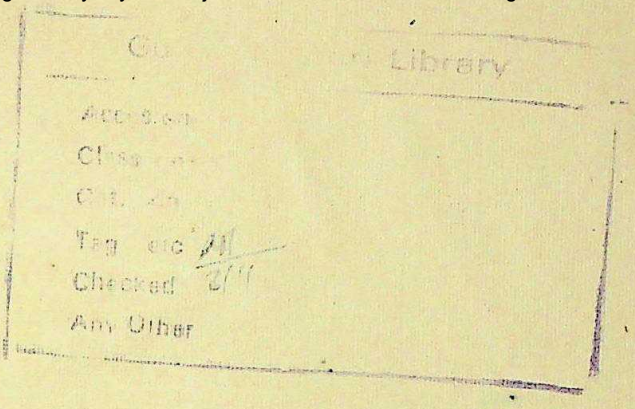

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

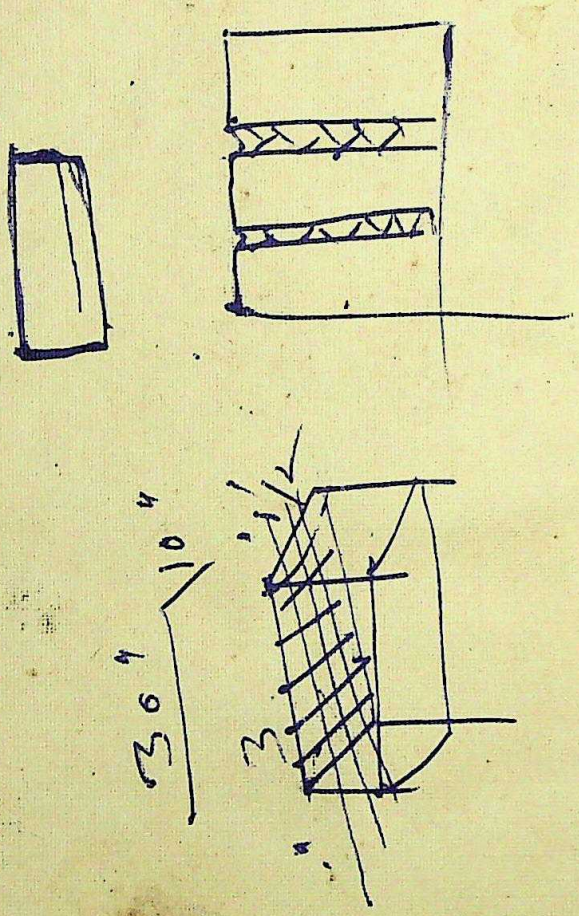

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

: અમદાવાદ

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar